आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1973)2

नागरिक विविध

हरबंस सिंह, मुख्य न्यायमूर्तिऔर गुरदेव सिंह, न्यायमूर्ति *के समक्ष*

प्रेम चंद आदि.-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य आदि,,-प्रतिवादी,

1971 की सिविल रिट संख्या 1221;

24 मई 1971.

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम (1957 का LXVII) - धारा 3 से 13 - पंजाब लघु खनिज रियायत नियम (1964) - नियम 5 से 33 - पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम (1837 का XVII) - धारा 42 - - "साल्टपीटर" "-क्या कोई लघु खनिज है - भूमि जिसमें लघु खनिज सरकार में निहित नहीं हैं - ऐसी भूमि में सॉल्टपीटर जीतने का अनुबंध

- क्या सरकार द्वारा दिया जा सकता है - सॉल्टपीटर के दोहन का अधिकार भूमि के मालिकों में निहित है - निर्धारण वाजिब-उल-अर्ज में प्रविष्टियाँ-क्या प्रासंगिक हैं।

अभिनिर्धारित किया 28 जनवरी, 1967 की अधिसूचना द्वारा, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ई) के तहत साल्टपीटर को प्रमुख खनिजों में से एक घोषित किया गया है। इसलिए साल्टपीटर प्रभाव से गौण खनिज है। 28 जनवरी, 1967, अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत।

(पैरा 10)

अभिनिर्धारित किया जिन भूमियों में गौण खनिज निहित होते हैं, उनके संबंध में नियमों के अलग-अलग सेट हैं, सरकार के पास और जिस भूमि में गौण खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास हैं, उसके संबंध में अलग-अलग नियम हैं। पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964 के नियम 5 से 33 के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार लघु खनिजों की प्राप्ति के लिए केवल तभी अनुबंध कर सकती है जब खनिज सरकार में निहित हों। खान और खनिज (विनियमन और

विकास) अधिनियम, 1S57, या पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसका प्रभाव सरकार में लघु खनिज के रूप में सॉल्टपीटर को निहित करने का हो, यदि अधिनियम से अलग हो और इसके नियम सरकार में निहित नहीं होते बल्कि किसी अन्य व्यक्ति में निहित होते हैं,

(पैरा 13)

अभिनिर्धारित किया इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए कि क्या किसी विशेष भूमि में नमक के दोहन का अधिकार सरकार या मालिकों में निहित है, पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान और उस विशेष गांव के वाजिब-उल-अर्ज की शर्तें यह देखना होगा कि जमीन कहां स्थित है।

(पैरा 24)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि विवादित अधिसूचना संख्या जीएलजी/एसपी/ऑक्टलॉन/

को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण, निषेध या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

483

682/70-7एल/88एल0-ए, दिनांक 25 फरवरी, 1971, गांव मयोली, तहसील कैथल, जिला करनाल के संबंध में, और प्रतिवादियों को गांव मयोली के शोरा क्षेत्र की नीलामी करने से प्रतिबंधित किया जाए और याचिकाकर्ताओं को बेदखल न किया जाए। ग्राम मयोली में याचिकाकर्ताओं के वैध कब्जे में हस्तक्षेप करने और नीलामी की पुष्टि नहीं करने के लिए। यह भी प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के अंतिम निपटान तक अंतरिम निषेधाज्ञा और स्थगन आदेश जारी किया जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अशोक सेन, अधिवक्ता, एस.के. जैन, अधिवक्ता,

न्यायमूर्ति.एन. कौशल, ए एडवोकेट-जी जनरल, हरियाणा, ए शोक बी हान, ए एडवोकेट, उत्तरदाताओं के लिए।

हरबंस सिंह, सी.न्यायमूर्ति. - यह निर्णय सिविल रिट संख्या: 1969 के 2559, 3575,3576, 3577, 3640, 3641, 3642 और 1970 के 3643, 10, 1209, 1214, 1215, 1216, 1221, 1246 का निपटान करेगा। 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1317, 1318, 1319, 1320, 1323, 1324 1328 1344, 1408, 1416, 1490, 1572, 1616 और 1679 का 1971, क्योंकि उनमें कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं तथ्य।

(2) उपर्युक्त सभी रिट याचिकाओं में यह मुद्दा उठाया गया है कि क्या राज्य सरकार प्रासंगिक कानून और नियमों के तहत मिट्टी में या व्यक्तियों या व्यक्तियों की भूमि की सतह पर पाए जाने वाले शोरा (नमकीन) का दोहन कर सकती है। ग्राम पंचायतें. 1971 की सिविल रिट 1221 को एक विशिष्ट मामले के रूप में लिया जाएगा जहां भूमि किसी व्यक्ति की थी और 1971 की सिविल रिट 1328 को एक विशिष्ट मामले के रूप में लिया जाएगा जहां भूमि संबंधित ग्राम पंचायत की थी।

(3) हम सबसे पहले 1971 के सिविल रिट 1221 को लेंगे। 25 फरवरी, 1971 को, आईयूडी "8टीईटीज़, हरियाणा विभाग द्वारा एक

अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया गया था कि विभिन्न गांवों में शोरा प्रभावित क्षेत्र हैं, उस अधिसूचना में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें ग्राम मयोली भी शामिल है जिसका उल्लेख क्रम संख्या 19 में किया गया है और इस रिट याचिका में हमारा संबंध किस गांव से है, 2 अप्रैल 1971 को सुबह 10 बन्यायमूर्ति कार्यालय में नीलामी के लिए रखा जाएगा। जिला उद्योग अधिकारी,पानीपत। अधिसूचना में नीलामी के नियमों और शर्तों का भी विवरण दिया गया है, जिनसे हमारा कोई लेना-देना नहीं है।

484

(4) वर्तमान रिट याचिका प्रेम चंद और एक अन्य द्वारा दायर की गई थी, जिसमें गांव मयोली में एक बड़े क्षेत्र के मालिक होने का दावा किया गया था, जिसका विवरण रिट याचिका के पैराग्राफ 2 में दिया गया है। यह आरोप लगाया गया कि राज्य न तो सॉल्टपीटर का मालिक था और न ही उसे इसकी नीलामी करने का कोई अधिकार था। अन्य बातों के अलावा यह आरोप लगाया गया कि इस गांव से संबंधित वाजिब-उल-

अर्ज में प्रविष्टियों के अनुसार, राज्य भूमि या भूमि में शोरा का मालिक नहीं है।

(5) राज्य की ओर से दायर रिटर्न में, यह विवादित नहीं था कि याचिकाकर्ता भूमि के मालिक हैं, लेकिन यह आग्रह किया गया था कि आरक्षण के आधार पर, सॉल्टपीटर के स्वामित्व का अधिकार सरकार में निहित है। 1904-09 में शरत वाजिब-उल-अर्ज़ द्वारा सरकार के पक्ष में पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 42 की उप-धारा (2) और खान और खनिज (विनियमन और विकास) के प्रावधानों के साथ पढ़ा गया: अधिनियम, 1957, और पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964।

(6) एक प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी कि रिट याचिका में तथ्य के जटिल प्रश्न शामिल थे और परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अतिरिक्त-दैनिक क्षेत्राधिकार को लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस आपत्ति को उस समय दबाया नहीं गया था उच्चतम न्यायालय के आधिपत्य द्वारा एक समान मामले में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर तर्क और अन्यथा कोई बल नहीं है। मूल रूप से

मामला, जो शोरा के शोषण से संबंधित था, ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य[1] और अन्य में इस न्यायालय के समक्ष आया था, (1) लेकिन याचिका को तुरंत खारिज कर दिया गया था और पारित आदेश इस प्रकार था;- .. .

''डॉ. शांति सरूप बनाम पंजाब राज्य [2]) और पंजाब हरियाणा शॉर्न फैक्ट्री आदि बनाम हरियाणा राज्य [3] में इस न्यायालय के पहले दो डिवीजन बेंच के फैसलों के बाद हम इस याचिका को खारिज करते हैं,''

- '

(7) उल्लिखित दो निर्णय इस आधार पर आगे बढ़े थे कि उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी याचिका पर निर्णय लेते समय, तथ्य के विवादित प्रश्नों पर विचार नहीं करेगा। इस न्यायालय

---

[1] 1969 के सी.डब्ल्यू. संख्या 2559 का निर्णय 30 सितंबर 1969 को हुआ।

[2] आई.एल.आर. 1969 (1) पी.बी. एवं घंटा 680.

[3] 1968 का सी.डब्लू. नं. 3405, 6 फरवरी 1969 को निर्णय हुआ,

ने राज्य को हलफनामा दायर करने के लिए नहीं बुलाया था और इस पर विचार नहीं किया था कि उठाए गए तथ्य जटिल थे या किसी अन्य कारण से रिट याचिका में विवाद की कोशिश करना अनुचित होगा। वास्तव में, राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया और सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा इसे इस प्रकार देखा गया: -

(4) एक्सआईएल 1967 एस.सी. 1081

(5) एक्सआईएल 1959 एस.सी., 149

(6) 1931 ए.सी. 662=ए.एल.एच. 1931 पी.सी. 24बी . . .

“इस न्यायालय में राज्य ने जवाब में एक हलफनामा दायर किया है; प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि तथ्य के ऐसे कोई जटिल प्रश्न थे जिनके लिए अपीलकर्ता को एक अलग मुकदमे में धकेलने की आवश्यकता होगी। यह भी बताया जा सकता है कि एक समान विवाद में सॉल्टपीटर

जीतने का अधिकार देने से भी संबंधित है। . ग्राम पंचायत का निर्णय उच्च के एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। 1969 के सी.डब्ल्यू. नंबर 1924 में कोर्ट ने ', आवेदक को राहत दी थी। हमारे विचार में उच्च न्यायालय कुल मिलाकर गलती में था। . अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को विनम्रतापूर्वक खारिज करते हुए।” .

रिमांड पर वापस प्राप्त यह रिट याचिका (सी.डब्ल्यू. 2559, 1969) भी निपटान के लिए हमारे समक्ष रखी गई रिट याचिकाओं में से एक है। ,"

(8) वास्तव में, इन याचिकाओं में तथ्य के कोई विवादित प्रश्न शामिल नहीं हैं, क्योंकि दोनों पक्ष शरत वाजिबुल-अर्ज पर भरोसा करते हैं और केवल विशेष के वाजिब-उल-उर्ज में प्रासंगिक स्थितियों की व्याख्या करना आवश्यक है। गाँव और पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का प्रभाव देखना।

(9) याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (बाद में केंद्रीय अधिनियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधान खानों और खनिजों के

विनियमन और विकास के लिए प्रदान करते हैं और यदि कोई विशेष खनिज राज्य सरकार में निहित नहीं है तो यह केंद्रीय अधिनियम उसे निहित करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। अब तक सवाल यह है कि क्या किसी विशेष खनिज पर अधिकार राज्य सरकार में निहित है या भूमि के मालिक में, मामले का निर्णय पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 42 के साथ पठित-वाजिब7उल-अर्ज के अनुसार किया जाना है, प्रतिवादी-राज्य की ओर से इस स्थिति का खंडन नहीं किया गया था।

(10) जहां तक केंद्रीय अधिनियम का संबंध है, धारा 3 परिभाषाएँ देती है और अन्य बातों के साथ-साथ खंड (ई) "लघु खनिजों" को निम्नानुसार परिभाषित करता है: - "

486

'लघु खनिज' का अर्थ है इमारती पत्थर, बजरी, साधारण • ; मिट्टी, निर्धारित प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली रेत के अलावा साधारण रेत, और कोई अन्य खनिज जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गौण खनिज घोषित कर सकती है;"

अधिसूचना, दिनांक 28 जनवरी, 1967 द्वारा शोरा को केंद्रीय अधिनियम की धारा 3(ई0) के तहत केंद्र सरकार द्वारा गौण खनिजों में से एक घोषित किया गया है। इस तथ्य को चुनौती नहीं दी जा रही है। इसलिए, शोरा एक गौण खनिज है। 28 जनवरी, 1967, केन्द्रीय अधिनियम के अर्थ में।

(11) केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 से 13 पूर्वेक्षण और खनन कार्य करने पर सामान्य प्रतिबंध प्रदान करती है, जो, हालांकि, धारा 14 के मद्देनजर, लघु खनिजों पर लागू नहीं होती है। धारा 15 राज्य सरकार को गौण खनिजों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति देती है। यह इस धारा के आधार पर था कि पंजाब गौण खनिज रियायत नियम, 1964 (इसके बाद पंजाब नियम के रूप में संदर्भित), के राज्यपाल द्वारा बनाए गए थे। पंजाब और 2 मई, 1964 को पंजाब गजट, असाधारण, भाग III में प्रकाशित (1964 लाहौर लॉ टाइम्स, खंड XLIII, पृष्ठ 102 में पुनर्मुद्रित)। पंजाब नियमों का नियम 2(बी) केंद्रीय अधिनियम की धारा 3 के समान शब्दों में 'लघु खनिज' को परिभाषित करता है। उक्त नियमों के अध्याय

II में नियम 5 से नियम 33 शामिल हैं, और इस अध्याय का शीर्षक निम्नानुसार है:

'उस भूमि के संबंध में खनन पट्टे/अनुबंध/अल्पकालिक परमिट प्रदान करना जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं।'

पंजाब नियमों के नियम 2 का खंड (न्यायमूर्ति) 'अनुबंध' को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता है: - "

'अनुबंध' का अर्थ सरकार की ओर से खुली नीलामी के माध्यम से या निदेशक द्वारा अधिसूचित कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए निविदाएं आमंत्रित करके, उसमें निर्दिष्ट किसी भी खनिज को ले जाने, जीतने, काम करने और ले जाने के लिए दिया गया अनुबंध है।

आगे के नियम 28 ऐसे अनुबंध देने की विधि से संबंधित हैं। अध्याय III का शीर्षक, जिसमें नियम 34 से आगे है, "उस भूमि के संबंध में खनिज रियायतें देना जिसमें लघु खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास निहित हैं।"

(12) इसलिए उन भूमियों के संबंध में अलग-अलग नियम हैं जिनमें लघु खनिज सरकार में निहित हैं और जिस भूमि में लघु खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में निहित हैं। यह आग्रह किया गया कि बाद के मामले में, सरकार के पास नीलामी या निविदा द्वारा अनुबंध देने का कोई अधिकार नहीं है। पंजाब नियमों के नियम 34 के आधार पर सरकार के पास केवल खनन पट्टों को देने को विनियमित करने की शक्ति है, लेकिन ये पट्टे पट्टादाता के नाम पर और उसके द्वारा दिए जाने चाहिए, जो वह व्यक्ति होगा जिसके पास गौण खनिज निहित हैं। . यह नियम 37 से स्पष्ट है जो इस प्रकार है:-

"खनन पट्टे की शर्तें - प्रत्येक खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा: -

(i) नियम 15, 18(3), 20, नियम 21(1) और 21(2) के खंड (i) से (xvi) (xviii) और (xviii) के प्रावधान संशोधन के साथ ऐसे पट्टों पर लागू होंगे। नियम 21 के उप-नियम (II) के खंड (ii) से (iv) और (xviii) में आने वाले शब्द "सरकार" को "पट्टादाता" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) पट्टे में ऐसी अन्य शर्तें शामिल हो सकती हैं जो इन नियमों के प्रावधानों के साथ असंगत न हों, जिन पर पार्टियों के बीच सहमति हो सकती है। * * *

(13) इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन नियमों के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार लघु खनिजों को जीतने के लिए केवल तभी अनुबंध कर सकती है जहां लघु खनिज सरकार में निहित हैं। इसके अलावा, यह सरकार के लिए आसान नहीं है कि केंद्रीय अधिनियम या पंजाब नियमों में ऐसा कोई प्रावधान है, जिसका प्रभाव केंद्रीय अधिनियम और पंजाब नियमों के अलावा, सरकार में लघु खनिज के रूप में सॉल्टपीटर को निहित करने का हो। , यह सरकार में निहित नहीं है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति में निहित है।

(14) इसलिए, हमें पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम के प्रावधानों और विशेष गांव के वाजिब-उल-अर्ज की शर्तों पर ध्यान देना होगा। पंजाब भू-राजस्व अधिनियम की धारा 42 निम्नलिखित प्रभाव वाली है:-

"(1) नवंबर, 1871 के अठारहवें दिन से पहले पूरा किए गए किसी भी अधिकार-रिकॉर्ड में, यह स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है कि

किसी भी जंगल, खदान, लावारिस, निर्वासित निर्जन या बंजर भूमि, सहज उपज या भूमि में अन्य सहायक हित भूमि-स्वामियों का है, यह सरकार का माना जाएगा।

(2) जब उस तिथि के बाद पूर्ण किए गए किसी भी अधिकार-रिकॉर्ड में यह स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है कि कोई जंगल या खदान या ऐसी कोई भूमि या हित सरकार का है, तो यह रेत-मालिकों का माना जाएगा।

(15) वर्तमान मामले में, वाजिब-उल-अर्ज, जिस पर भरोसा किया जाता है। दोनों पक्षों का मामला 1904-09 का है और इसलिए, पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) ही लागू होगी।

(16) पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के तहत उत्पन्न होने वाली धारणा के अलावा, विद्वान वकील द्वारा राजा आनंद ब्रह्मा शाह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा मान्यता प्राप्त सामान्य धारणा पर भी निर्भरता रखी गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (4), पृष्ठ 1088 पर, कि प्रथम दृष्टया भूमि-मालिक खनिजों के भी मालिक हैं। बशेशर नाथ बनाम आयकर आयुक्त, (5) में,

सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने एशुगबायी एलेको बनाम नाइजीरिया सरकार के प्रशासन अधिकारी (6) में लॉर्ड एटकिन की टिप्पणी को मंजूरी के साथ उद्धृत किया, "यह ब्रिटिश न्यायशास्त्र के अनुसार है।" कार्यपालिका का कोई भी सदस्य ब्रिटिश प्रजा की स्वतंत्रता या संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि जब वह न्यायालय के समक्ष अपने कार्य की वैधता का समर्थन कर सके।

(17) याचिकाकर्ताओं की ओर से इस बात पर भी जोर दिया गया कि जंगल, खदानों, भवन निर्माण के पत्थर, बजरी, रेत आदि के विपरीत, जिन्हें आम तौर पर सरकार द्वारा अपने में निहित माना जाता था, यह सरकार की नीति थी कि वह ऐसा न करे। सॉल्टपीटर को सरकार में निहित करने के रूप में। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में डौई के पंजाब सेटलमेंट मैनुअल, पैराग्राफ 193, पृष्ठ 96 का हवाला दिया। अनुच्छेद 193 इस प्रकार चलता है:— -

''साल्टपीटर को सरकारी संपत्ति नहीं माना जाता। - साल्टपीटर में सरकार के अधिकारों का सवाल 1891 में हिसार जिले के निपटान के

संबंध में उठाया गया था, जब पंजाब सरकार ने माना था कि न तो साल्टपीटर मिट्टी और न ही तैयार साल्टपीटर को उचित रूप से लाया जा सकता है। भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 42 के अर्थ में "भूमि में सहज उपज या अन्य सहायक हित" शब्द के तहत। यह जोड़ा गया कि सर न्यायमूर्तिम्स लायल का मानना था कि "व्यवहार में पंजाब में कहीं भी सरकार शोरा भूमि पर मालिकाना अधिकार, या शोरा पैदा करने के अधिकारों पर एकाधिकार का दावा नहीं करती है, हालांकि पूर्ववर्ती देशी सरकारों ने इस तरह के शीर्षक का दावा किया होगा। सरकार जो भी दावा करती है वह विनिर्माण को विनियमित करने या रोकने का अधिकार है। इसलिए, सॉल्टपीटर या शोरा को ग्राम प्रशासन के कागजात में सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, और भूमि-मालिकों को इससे प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ को भूमि-राजस्व का आकलन करते समय ध्यान में रखा जा सकता है। यदि किसी भी कारण से उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता है तो इस तथ्य को स्पष्ट रूप से नोट किया जाना चाहिए कि सरकार ने भविष्य में किसी समय उनका मूल्यांकन करने का अपना अधिकार नहीं छोड़ा है।

इस अनुच्छेद में संदर्भित ग्राम प्रशासन पत्र को वाजिब-उल-अर्ज कहा जाता है, और इसे डौई के पंजाब सेटलमेंट मैनुअल के पृष्ठ 152 पर अनुच्छेद 295 में निपटाया गया है। इसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"वाजिब-उल-अर्ज, या ग्राम प्रशासन पत्र, संपत्ति में अधिकारों और देनदारियों के संबंध में मौजूदा रीति-रिवाजों का रिकॉर्ड होना चाहिए। इसका उपयोग नए अधिकारों या देनदारियों के निर्माण के लिए या जिसे ग्राम कानून कहा जा सकता है, के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 296 प्रारंभिक बस्तियों के वाजिब-उल-अर्ज के बारे में कुछ टिप्पणी करता है और इसमें उल्लेख किया गया है कि ऐसा वाजिब-उल-अर्ज "कभी-कभी एक दुर्जेय दस्तावेज था लेकिन गांव के रीति-रिवाजों के सबूत के रूप में इसका वास्तविक मूल्य हमेशा इसकी लंबाई के अनुपात में नहीं था" , और नीचे एक नोट है कि "विषय पर मौजूदा नियम परिशिष्ट VIII-E में पुन: प्रस्तुत किए गए हैं"।

(18) अब परिशिष्ट VIII-E इसी मैनुअल में पेज lxx (70) पर दिया गया है और यह स्पष्ट जानकारी देता है कि वाजिब-उल-अर्ज में किन

मामलों को और किस क्रम में दर्ज किए जाने की उम्मीद है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

"(1) संपत्ति पर अधिकारों और देनदारियों का सम्मान करने वाले सीमा शुल्क का विवरण कथात्मक रूप में होगा; यह उतना संक्षिप्त होगा जितना विषय की प्रकृति स्वीकार करती है, और तर्कपूर्ण नहीं होगा, बल्कि उन रीति-रिवाजों के एक सरल विवरण तक ही सीमित होगा जिनका अस्तित्व सुनिश्चित है। कथन को क्रमिक रूप से क्रमांकित पैराग्राफों में विभाजित किया जाएगा, प्रत्येक पैराग्राफ का यथासंभव अलग-अलग वर्णन किया जाएगा।

(2) विवरण में कानून द्वारा विनियमित मामलों से संबंधित प्रविष्टियाँ नहीं होंगी, न ही न्याय, समानता, या अच्छे विवेक के विपरीत रीति-रिवाज, या जिन्हें किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा शून्य घोषित किया गया

हो, इसमें दर्ज नहीं किए जाएंगे। इन प्रतिबंधों के अधीन, विवरण में संपत्ति से संबंधित निम्नलिखित कई मामलों की जानकारी होनी चाहिए: ■—

(ए) सामान्य भूमि, इसकी खेती और प्रबंधन, और इसकी आय का आनंद।

(बी) सामान्य भूमि पर चराई का अधिकार।

(सी) कहने वाले की उपज के आनंद का अधिकार।

(डी) ग्राम व्यय (मालबा) से संबंधित उपयोग।

(ई) भूमि की सिंचाई से संबंधित सीमा शुल्क। (एफ) मिलों, टैंकों, जलधाराओं से संबंधित सीमा शुल्क; या प्राकृतिक जल निकासी।

(छ) जलोढ़ और जलोढ़ की प्रथा।

(ज) कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए सभी वर्गों के कृषकों के अधिकार (उदाहरण के लिए, पेड़ों या खाद के अधिकार, और पेड़ लगाने का अधिकार) और लगान के अलावा उनकी प्रथागत देनदारियां।

(i) ग्राम सेवकों को देय प्रथागत देय राशि और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रथागत सेवा।

(न्यायमूर्ति) किसी भी नजूल संपत्ति, जंगल, लावारिस, निर्वासित, निर्जन या बंजर भूमि पर सरकार के अधिकार; खदानें; संपत्ति की सीमाओं के भीतर शामिल भूमि में पुरातात्विक रुचि के खंडहर या वस्तुएं, सहज उत्पाद और अन्य सहायक रुचि।

(के) नदियों आदि में मछली और मत्स्य पालन के संबंध में सरकार के अधिकार।

(एल) भूमि मालिकों, कृषकों या संपत्ति में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई अन्य महत्वपूर्ण उपयोग, जो भूमि संपत्ति के उत्तराधिकार और हस्तांतरण से संबंधित उपयोग नहीं है।

वाजिब-उल-अर्ज में शामिल विभिन्न मामलों को इंगित करने के लिए हमने पूरे पैराग्राफ 2 को दोबारा तैयार किया है। वर्तमान मामले में हम ऊपर उल्लिखित पैराग्राफ 2 के खंड (सी) और (न्यायमूर्ति) से चिंतित हैं। खंड (न्यायमूर्ति!) के तहत किसी भी नजूल संपत्ति, जंगलों, बंजर भूमि, खदानों पर सरकार के अधिकार दर्ज हैं; आदि आदि।

(19) जिस रिट याचिका पर हम अब विचार कर रहे हैं, उसमें राज्य की ओर से खंड (न्यायमूर्ति) यानी खंड 10 से संबंधित वाजिब-उल-अर्ज़ से केवल एक उद्धरण प्रस्तुत किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार इस धारा की शब्दावली पर भरोसा करती है। जहां तक इस गांव का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा दायर खंड 10 [खंड (न्यायमूर्ति) के अनुरूप], अनुबंध 'ए' का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: - ,

लेकिन नजूल संपत्ति, पत्थरों की खदानें, चूना, कंकर और सभी प्रकार के छोटे पत्थर जो जमीन के नीचे या ऊपर पाए जाते हैं, सरकार की हैं। अब तक जो भी कंकड़ मिले हैं या भविष्य में मिलेंगे वे सभी सरकार के हैं।”

(20) याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया कि वास्तविक खंड खंड (सी) होगा, क्योंकि भूमिगत जल में शोरा और अन्य अधिकारों का निपटारा इसी खंड के तहत किया जाना है। इस संबंध में डौई सेटलमेंट मैनुअल के पृष्ठ 182 पर पैराग्राफ 356 का संदर्भ दिया गया है। इस अनुच्छेद का शीर्षक है:

"भूमि से जुड़े आय के विविध स्रोत।"

इस पैराग्राफ का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

"अब तक हम केवल मिट्टी के कृषि किराये पर विचार कर रहे हैं, लेकिन मालिक, इसके अलावा, अपशिष्ट और खेती योग्य भूमि के सहज उत्पादों से, जल शक्ति के पट्टे से या नमक निकालने के अधिकार से आय प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी आदि। कृषि किराये के अलावा लाभ की ऐसी सभी वस्तुओं को बस्ती की भाषा में सेयर (अरबी शब्द सायर से जिसका अर्थ है प्रकट रहना) या सेवई के रूप में जाना जाता है। यदि उनका कोई महत्व है, तो शुद्ध संपत्ति की गणना में उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। * * * *

(21) तर्क यह था कि याचिकाकर्ताओं की भूमि में हस्तक्षेप को उचित ठहराना सरकार का काम है और ऐसी कोई धारणा नहीं है कि धारा 42 की उपधारा (2) के मद्देनजर सॉल्टपीटर के संबंध में अधिकार सरकार में निहित है। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम के अनुसार, जब तक ऐसे अधिकार विशेष रूप से सरकार में निहित नहीं होते, तब तक यह माना जाता है कि वे भूमि के मालिक में निहित हैं। कहने वालों के

अधिकारों से संबंधित वाजिब-उल-अर्ज के प्रासंगिक खंड को प्रस्तुत करके इस धारणा का खंडन किया जा सकता था। दरअसल, विद्वान वकील ने सिविल रिट 1246 में दायर हिजरनवां कलां गांव के वाजिब-उल-अर्ज के उद्धरण का हवाला दिया। इस उद्धरण (अनुलग्नक 'ए') में उस गांव के वाजिब-उल-अर्ज का खंड 3 दिया गया है। पुनरुत्पादित और यह विशेष रूप से शोरा से संबंधित है। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि तथ्य यह है कि वर्तमान याचिका में राज्य सरकार ने वाजिब-उल-अर्ज के खंड 3 को प्रस्तुत नहीं किया है, यह अनुमान लगाता है कि विवाद में खंड सरकार के विवाद के खिलाफ है। नतीजतन, यह आग्रह किया गया कि इस रिट याचिका में यह माना जाना चाहिए कि सॉल्टपीटर सरकार में निहित नहीं है।

(22) 1971 के सिविल रिट 1328 को जन्म देने वाले तथ्य कमोबेश एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि इस मामले में याचिकाकर्ता ओम प्रकाश,

ग्राम पंचायत के पट्टेदार हैं और जिस भूमि से शोरा निकाला जाना है वह शमिलत है भूमि जो पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलेशन) अधिनियम, 1953 (1954 का अधिनियम 1) के आधार पर बाद में 1964 के पंजाब अधिनियम संख्या 19 द्वारा संशोधित पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) अधिनियम, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित की गई, में निहित है ग्राम पंचायत. पहले शमिलत ज़मीन सभी मालिकों हसब रसद खेवत की होती थी, यानी ज़मीन के मालिकाना हक़ के हिस्से के हिसाब से। पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 (इसके बाद पंजाब एक्ट 19611 के रूप में संदर्भित) के तहत, ऐसी भूमि अब ग्राम पंचायत में निहित है। हालाँकि, एक बात स्पष्ट है कि 1961 का पंजाब अधिनियम या 1954 का पूर्ववर्ती अधिनियम संख्या 1 किसी भी तरह से शमिलत भूमि का कोई अधिकार सरकार में निहित नहीं करता है, जो मूल रूप से मालिकों में निहित था।

(23)सिविल रिट क्रमांक 1328 सन् 1971 में, प्रश्नाधीन भूमि ग्राम मलार में स्थित है। यहां भी वाजिब-उल-अर्ज का केवल खंड 10 ही तैयार किया गया है, जिसमें शोरा का कोई विशेष उल्लेख नहीं है।

(24) हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता श्री जगन नाथ कौशल ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा संबोधित तर्कों की ताकत को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया और आग्रह किया कि धारा 42 की उप-धारा (2) के तहत केवल एक धारणा उत्पन्न होती है। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, कि जहां वाजिब-उल-अर्ज में स्पष्ट रूप से भूमि में कुछ अधिकार सुरक्षित रखने का कोई उल्लेख नहीं है, तो ऐसे अधिकार सरकार में नहीं बल्कि भूमि के मालिक में निहित हैं और यह धारणा हो सकती है साक्ष्य प्रस्तुत कर खंडन किया। लिखित बयान में सरकार ने अपने दावे को पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अलावा वाजिब-उल-अर्ज पर ही आधारित किया है। तो यह केवल वाजिब-उल-अर्ज में प्रविष्टियाँ हैं जो इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए प्रासंगिक होंगी कि क्या शोरा या सॉल्टपीटर मिट्टी युक्त सरकार में निहित है। हालाँकि, विद्वान महाधिवक्ता ने थोड़े समय के लिए स्थगन की प्रार्थना की ताकि वह उन विभिन्न गाँवों के मूल वाजिब-उलरज़ को अदालत में पेश कर सकें जिनके संबंध में रिट दायर की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि अधिकांश याचिकाकर्ता और राज्य वाजिब-उल-

अर्ज में केवल प्रविष्टि 10 (खंड 'न्यायमूर्ति') पर भरोसा करते थे और यह केवल बहुत कम मामलों में था कि याचिकाकर्ताओं ने कॉलम नंबर में प्रविष्टि की प्रतियां लगाईं। 3. यदि वाजिब-उल-अर्ज के कॉलम नंबर 3 में यह पाया जाता है कि शोरा के दोहन का अधिकार मालिकों में निहित है, तो जाहिर तौर पर राज्य अपने दावे पर जोर देने की स्थिति में नहीं होगा कि ये अधिकार राज्य में निहित हैं। सरकार। हालाँकि, यदि कॉलम नंबर 3 में प्रविष्टि इस मामले के बारे में मौन है और कॉलम नंबर 10 में भी किसी न किसी तरह से शोरा के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है, तो न्यायालय के लिए यह निर्धारित करना एक प्रश्न होगा कि क्या कॉलम नंबर 10 में प्रविष्टि में प्रयुक्त शब्दों का तात्पर्य, यदि स्पष्ट रूप से नहीं तो, सरकार के पक्ष में सॉल्टपीटर के दोहन का अधिकार सुरक्षित है। दूसरी ओर, यदि प्रविष्टि संख्या 3 मौन है और कॉलम संख्या 10 की प्रविष्टि में एक विशिष्ट उल्लेख है, कि सॉल्टपीटर पर अधिकार सरकार में निहित है तो यह सरकार के पक्ष में एक स्पष्ट आरक्षण होगा। नतीजतन, उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें मूल वाजिब-उल-अर्ज पेश करने के लिए समय दिया जाए ताकि मामला स्पष्ट हो सके। हमने महसूस

किया कि इन रिट याचिकाओं के संतोषजनक निर्णय के लिए, संबंधित विभिन्न गांवों के वाजिब-उल-अर्ज में प्रविष्टियों को देखना हमारे लिए उपयोगी और वास्तव में आवश्यक होगा - परिणामस्वरूप, मामला स्थगित कर दिया गया और विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा ने हमारे सामने वाजिब-उल-अर्ज पेश किया।

(25) जैसा कि ऊपर बताया गया है, विभिन्न गांवों के वाजिब-उल-अर्ज में प्रविष्टियां तीन अलग-अलग श्रेणियों में आती हैं। केवल दो गाँव पनिहारी और मुसैबवाला हैं जो तीसरी श्रेणी में आते हैं, अर्थात्, जहाँ कॉलम नंबर 3 में शोरा से किसी भी आय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन कॉलम नंबर 10 में शोरा और शोरा युक्त मिट्टी विशेष रूप से सरकार के लिए आरक्षित हैं। कांकर की सभी प्रकार की खदानों के अतिरिक्त। पत्थर, आदि- जहां तक इन दोनों गांवों का संबंध है; विद्वान महाधिवक्ता ने जोरदार आग्रह किया कि यहां वाजिब-उल-अर्ज ने इन अधिकारों को स्पष्ट रूप से राज्य सरकार के लिए आरक्षित रखा है और

कॉलम नंबर 3 में इसके विपरीत कोई प्रविष्टि नहीं है। वर्ष 1919-20 की मूल प्रविष्टियां प्रस्तुत की गईं और प्रतियां बनाई गईं संबंधित फाइलों पर रख दिया गया है। सिविल रिट संख्या 1318/1971 ग्राम पंचायत, पनिहारी के पट्टेदार द्वारा दायर की गई है, और सिविल रिट संख्या 1320/1971 ग्राम सभा, पनिहारी द्वारा दायर की गई है। 1971 की सिविल रिट संख्या 1319 ग्राम मुसैबवाला में स्थित भूमि के पट्टेदार द्वारा दायर की गई है, जिसे पनिहारी की ग्राम पंचायत द्वारा नीलाम भी किया गया था, जिसका स्पष्ट रूप से ग्राम मसाइबवाला पर अधिकार क्षेत्र था। इन तीन रिट याचिकाओं के संबंध में, इसलिए, विवाद में भूमि पर सॉल्टपीटर सरकार में निहित होने का आरोप लगाया गया है। (26) इन मामलों में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आर.एस. मितल ने पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट की धारा 3 का हवाला दिया। 1953 (1954 का पंजाब अधिनियम संख्या 1), जिसे इसके बाद 1954 का पंजाब अधिनियम और 1961 के पंजाब अधिनियम की धारा 4 के रूप में जाना जाता है, जैसा कि बाद में संशोधित किया गया, और आग्रह किया कि इन दोनों धाराओं को एक साथ पढ़ने से पता चलेगा कि

इनमें अधिकार हैं किसी भी रीति-रिवाज या समझौते के विपरीत किसी भी बात के बावजूद शामिलाट भूमि पंचायत में निहित हो जाती है। इसलिए, उन्होंने आग्रह किया कि यदि शमिलत भूमि पर सरकार का कोई अधिकार है, तो वह भी पंचायत में निहित है।

495

(27) 1954 के पंजाब अधिनियम की धारा 3 निम्नानुसार चलती है: - "तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, और किसी भी समझौते, साधन, प्रथा या उपयोग या किसी डिक्री या आदेश के बावजूद कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी, भूमि के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित-

(ए) जो किसी गांव के शामलात देह में शामिल है, नियत तिथि पर गांव पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली पंचायत में निहित हो जाएगा;

(बी) जो एक गांव के आबादी देह में स्थित है और जो एक गैर-मालिक के स्वामित्व वाले घर के अंतर्गत है, अधिनियम के प्रारंभ में उक्त गैर-मालिक में निहित होगा।

इसके बाद, 1961 के पंजाब अधिनियम में 'शामिलत भूमि' की परिभाषा में थोड़ा बदलाव किया गया और इसकी धारा 4 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

"(1) किसी अन्य कानून में या किसी समझौते, साधन, प्रथा या उपयोग या किसी अदालत या अन्य प्राधिकारी के किसी डिक्री या आदेश में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, सभी अधिकार, शीर्षक और हित जो भी हों भूमि-

(ई) जो किसी गांव के शामिलात देह में शामिल है और जो शामिलात कानून के तहत किसी पंचायत में निहित नहीं है, इस अधिनियम के प्रारंभ में, ऐसे गांव के लिए गठित पंचायत में निहित होगा, और जहां ऐसी कोई पंचायत नहीं है ऐसे गांव के लिए गठित पंचायत में निहित ***** *

(बी) * * * * * *

(2) और भूमि जो शमिलत कानून के तहत पंचायत में निहित है, इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित मानी जाएगी।

'शमिलात कानून' जहां तक इस मामले के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है, पंजाब अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (एच) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है; —

"(ज) 'शमिलात कानून' का अर्थ है-

(i) उस क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में, जो 1 नवंबर 1956 से ठीक पहले, पंजाब राज्य में शामिल थी, पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1953;

(ii)* * * * * > >

496

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1973)2

1981 के पंजाब अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के आधार पर, कोई भी भूमि जो 1954 के पंजाब अधिनियम के तहत पंचायत में निहित थी, "इसके तहत पंचायत में निहित मानी जाएगी। अधिनियम" और यह निहितार्थ अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी समझौते, लिखत, प्रथा या उपयोग में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद होता है।

(28) इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्रावधान एक तर्क को जन्म दे सकता है कि कोई भी अधिकार जो वाजिब-उल-अर्ज या ग्राम प्रशासन पत्र में कही गई किसी बात के आधार पर सरकार में निहित है, वह पंचायत में भी निहित होगा, क्योंकि अधिकार निहित हैं किसी भी समझौते, उपकरण, प्रथा या उपयोग के बावजूद और वाजिब-उल-अर्ज आवश्यक रूप से इनमें से एक या अन्य श्रेणियों के अंतर्गत आना चाहिए। हालाँकि, पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) द्वारा इस अधिनियम में बाद में किए गए संशोधन के कारण, ऐसे सभी संदेह दूर हो गए हैं। संशोधन अधिनियम, 1964 (1964 का 19), जिसके द्वारा धारा 14-ए जोड़ी गई और, इस धारा का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार चलता है: -

"इस अधिनियम या शामिलात कानून में कुछ भी शामिल नहीं होगा-

(ए) इस अधिनियम के तहत किसी पंचायत में निहित या निहित समझी जाने वाली भूमि पर राज्य सरकार के किसी भी अधिकार को प्रभावित करेगा या प्रभावित करेगा; -

(बी) ***** *"_

अत: याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलील में कोई दम नहीं है।

(29) इस प्रकार, जहां तक पनिहारी और मुसैबवाला गांवों का संबंध है, वाजिब-उल-अर्ज के अनुसार, नमक और शोरा युक्त मिट्टी सरकार में निहित है और, परिणामस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा भूमि की नीलामी के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वैध हैं। 1971 की सिविल रिट संख्या 1318, 1319 और 1320 को खारिज करना होगा।

(30) शेष रिट याचिकाएँ दो व्यापक श्रेणियों में आती हैं। मामलों की पहली श्रेणी में वाजिबुल-अर्ज़ के कॉलम नंबर 3 में प्रविष्टि स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि शोरा से होने वाली आय मालिकाना निकाय की है और कॉलम नंबर 10 में सॉल्टपीटर या मिट्टी वाले शोरा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। इस बात पर संदेह किया जा सकता है कि, जहां तक

इन मामलों का संबंध है, राज्य सरकार के पास कोई भी आसानी नहीं है और वह इन जमीनों से सॉल्टपीटर की जीत के संबंध में अनुबंध नहीं दे सकती है। इस श्रेणी में कई रिट याचिकाएँ आती हैं। गांव हिजरांवां से संबंधित 1971 की सिविल रिट 1246, गांव जुताबाध से संबंधित 1971 की सिविल रिट संख्या 1247, भवाद गांव से संबंधित 1971 की सिविल रिट 1616, गांव अयाल्की से संबंधित सिविल रिट 1679 और गांव रनिया से संबंधित 1970 की सिविल रिट 3643 और इस श्रेणी से संबंधित कुछ याचिकाएँ।

(31) अधिकांश अन्य मामले दूसरी श्रेणी में आते हैं, जहां मालिकों द्वारा प्राप्त किसी भी आय का कॉलम नंबर 3 में कोई उल्लेख नहीं है और कॉलम नंबर 10 में सॉल्टपीटर के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। विद्वान महाधिवक्ता ने ग्राम कल्पा से संबंधित 1971 के सिविल रिट 10 को इस श्रेणी के एक विशिष्ट मामले के रूप में लिया। यहां वर्ष 1909 के वाजिब-उल-अर्ज के कॉलम नंबर 3 में कहा गया है कि कहने वाले की कोई आय नहीं है। वाजिब-उल-अर्ज़ (अनुलग्नक आर. 1) के कॉलम नंबर 10 में क्या उल्लेख किया गया है:

“जो कंकर पत्थर वघैरा ज़मीन के ऊपर या नीचे हो वो सब मलकियत सरकार हैं।”

(जमीन के नीचे या ऊपर कंकर, पत्थर आदि की जो भी खदानें होंगी वे सभी सरकार की होंगी।^

(32) विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि वर्ष 1963-64 और यहां तक कि 1969-70 में भी वही प्रविष्टियाँ दोहराई गई हैं। विद्वान महाधिवक्ता का तर्क यह था कि जब आम तौर पर यह कहा जाता है कि कंकर और पत्थर आदि की सभी खदानें, जो भूमि के नीचे या ऊपर हो सकती हैं, सरकार की हैं, तो जोड़े गए शब्द 'आदि' में सभी प्रकार की खदानें शामिल होनी चाहिए। सामग्री, जो भूमि के नीचे या ऊपर पाई जा सकती है, जिसमें सॉल्टपीटर भी शामिल है, क्योंकि यह विशेष रूप से मालिकों के लिए आरक्षित नहीं है। यह व्याख्या पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के प्रावधानों और डौई के पंजाब निपटान मैनुअल के अनुच्छेद 193 के प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज करती है, जो सॉल्टपीटर के संबंध में सरकार के रवैये के बारे में स्पष्ट जानकारी देती है। अनुच्छेद 193 के स्पष्ट शब्दों में कोई

संदेह नहीं है कि नीति के एक मामले के रूप में सरकार ने सॉल्टपीटर या सॉल्टपीटर वाली मिट्टी पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं करने का निर्णय लिया है और इस स्रोत से प्राप्त किसी भी आय को केवल उसी के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। मूल्यांकन उद्देश्य. उपर्युक्त अनुच्छेद 193 में पहले से ही पुनरुत्पादित निम्नलिखित शब्दों पर और जोर दिया गया है: -

498

“* * सरकार जो भी दावा करती है वह विनिर्माण को विनियमित करने या रोकने का अधिकार है। इसलिए, सॉल्टपीटर या सॉर्न को ग्राम प्रशासन के कागज में सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, और भूमि मालिकों को इससे प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ को भू-राजस्व का आकलन करते समय ध्यान में रखा जा सकता है। * * # # »

(33) यह मामला है और राज्य सरकार के पक्ष में शोरा के लिए कोई आरक्षण नहीं है, इस आरक्षण को "वागैरा' (आदि) शब्द में लाना मुश्किल है। इससे भी अधिक जब उसी जिले के अन्य गांवों के वाजिबुल-

अर्ज़ में, और वास्तव में, उसी तहसील गोहाना में, कॉलम नंबर 3 में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि शोरा की नीलामी की जाती है और मालिकों के बीच आय वितरित की जाती है (देखें) यह ग्राम भवाद, तहसील गोहाना, जिला रोहतक से संबंधित 1971 की सी.डब्ल्यू. 1616 के संबंध में है)। इस प्रकार, राजस्व अधिकारी, जो जिले में वाजिब-उल-अर्ज तैयार कर रहे थे, इस तथ्य से पूरी तरह अवगत थे कि शोरा पर अधिकार कंकर और पत्थरों पर अधिकार से अलग थे और आम तौर पर कॉलम नंबर 3 में उल्लेख किया जाना था। अत: विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(34) एक और उप-श्रेणी है जो इस व्यापक श्रेणी में आती है। ये ऐसे मामले हैं जहां 1919 के सेटलमेंट में कॉलम नंबर 3 में किसी कहने वाले के अधिकारों के बारे में कोई जिक्र नहीं है, या यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे कोई अधिकार नहीं हैं। कॉलम नंबर 10 के सामने की प्रविष्टि में शोरा का भी कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन 1880-82 के पहले के समझौते में कॉलम नंबर 3 में स्पष्ट उल्लेख था कि मिट्टी युक्त शोरा और शोरा सरकार में निहित हैं। तथ्य यह है कि बाद के समझौते

में सॉल्टपीटर और सॉल्टपीटर वाली धरती को बाहर रखा गया है, बल्कि यह दर्शाता है कि सॉल्टपेर पर किसी भी मालिकाना अधिकार का दावा न करने की सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप, वाजिब-उल-अर्ज को बाद के समझौते में सही किया गया था। समझौता। इस व्यापक श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में, जिनमें कॉलम नंबर 3 में शोरा से होने वाली किसी भी आय का कोई उल्लेख नहीं है और कॉलम नंबर 10 में किसी में या नवीनतम वाजिब-उल-अर्ज़ में भी कोई उल्लेख नहीं है। , पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के आधार पर यह धारणा होगी कि अधिकार मालिकों में निहित हैं न कि सरकार में। इस प्रकार इन दोनों श्रेणियों में आने वाली सभी रिट याचिकाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा जारी नीलामी के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

(35) एक अनोखा मामला था, जो हमारे संज्ञान में लाया गया था और वह 1970 का सिविल रिट 3577 है जो गांव ओट्टू, जिला हिसार से संबंधित है। यहां वर्ष 1919-20 के वाजिब-उल-अर्ज में कॉलम नंबर 3 में इसका उल्लेख इस प्रकार है: -

“रुपये की आमदनी है. शोरा से 100 रु. प्राप्त होते हैं जो स्वामियों को उनके स्वामित्व के अनुपात में प्राप्त होते हैं। कोई अन्य आय नहीं है।”

इस प्रकार, एक स्पष्ट और विशिष्ट उल्लेख है कि शोरा मालिकों में निहित है। हालाँकि, आश्चर्यजनक रूप से, वाजिब-उल-अर्ज के कॉलम नंबर 10 में, प्रविष्टि उसी प्रकार की है जैसा कि 1971 के सिविल रिट 1318 और 1320 में पाया गया था, जो कि पनिहारी गाँव से संबंधित है, जिसका निपटारा ऊपर किया गया है। प्रविष्टि इस प्रकार है: - "धातु, पत्थर, कंकर, कोयला, शोरा और शोरा की खदानें जो भूमि के ऊपर या नीचे हैं, राज्य की होंगी।"

(36) ये दोनों प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से विरोधाभासी हैं। यदि सॉल्टपीटर और सॉल्टपीटर वाली मिट्टी से होने वाली आय मालिकों को प्राप्त हो रही है, तो सॉल्टपीटर और सॉल्टपीटर वाली मिट्टी एक ही समय

में संभवतः सरकार में निहित नहीं हो सकती है। इन दोनों प्रविष्टियों में सामंजस्य बिठाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन डौई के पंजाब सेटलमेंट मैनुअल में दिए गए पैरा 193 और परिशिष्ट VIII-ई को ध्यान में रखते हुए; ऊपर दिए गए पुनरुत्पादन में, सॉल्टपीटर आदि से संबंधित अधिकारों का उल्लेख कॉलम नंबर 3 में किया जाना चाहिए, न कि कॉलम नंबर 10 में और, परिणामस्वरूप, कॉलम नंबर 3 में प्रविष्टि कॉलम नंबर 10 में प्रविष्टि को प्रतिस्थापित कर देगी। इस मामले में इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता कि सॉल्टपीटर और सॉल्टपीटर वाली मिट्टी के संबंध में अधिकार सरकार में निहित हैं। इस रिट याचिका को भी स्वीकार किया जाना चाहिए और नीलामी के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

(37) अब हम 1969 की सिविल रिट 2559 से निपट सकते हैं, जिसे वाई द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय ने इस आधार पर कि इसमें तथ्य का विवादित प्रश्न शामिल है, जिसे 1969 की सिविल अपील संख्या 2542 (ओम प्रकाश वाई. हरियाणा राज्य और अन्य), 16 मार्च, 1910 को निर्णय लिया गया।

(38) यह याचिका मलार और प्यौदा गांव स्थित जमीन के पट्टेदार ओम प्रकाश ने दायर की है. जिस अवधि के लिए पट्टा दिया गया था और जिसके संबंध में यह रिट याचिका दायर की गई थी वह 1 अगस्त, 1968 से 31 जुलाई, 1970 तक थी, जो अवधि पहले ही बीत चुकी है। इसी ओम प्रकाश द्वारा बाद की अवधि के लिए दो अन्य रिट याचिकाएं दायर की गई हैं, अर्थात्, मलार गांव से संबंधित 1971 की सिविल रिट 1328 और 1344। 1971 की सिविल रिट 1572 ग्राम सभा, प्यौदा द्वारा दायर की गई है, और यह रिट ग्राम प्यौदा से संबंधित है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, ये तीन रिट याचिकाएँ स्वीकार की जा रही हैं। 1969 की सिविल रिट 2559 में भूमि का कब्ज़ा याचिकाकर्ता के पास ही रहा। उन्होंने रुपये की जमानत राशि जमा की थी. इस मामले में फैसला याचिकाकर्ता के खिलाफ और राज्य सरकार के पक्ष में जाने पर राज्य सरकार को 58,000 रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। हालाँकि, यह याचिका उस अवधि

से संबंधित है जो पहले ही बीत चुकी है, इसे भी स्वीकार किया जाना चाहिए और सुरक्षा रद्द कर दी जाएगी। §एस*आर.

(39) ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, 1971 की सिविल रिट 1318. 1319 और 1320 को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है, जबकि सिविल रिट 3575, 3576, 3577, 3640; 1970 के 3641, 3642 और 3643, सिविल रिट 10, 1209, 1214, 1215, 1216, 1221, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252; 1971 की 1253, 1254, 1317, 1323, 1324, 1328, 1344, 1408, 1416, 1490, 1572, 1616 और 1679 और 1969 की सिविल रिट 2559 को लागत के साथ स्वीकार किया जाता है और नीलामी के आदेश रद्द कर दिए जाते हैं।

गुकदेव सिंह, न्यायमूर्ति.-मैं सहमत हूं।

बी.एस.जी.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

पानीपत, हरियाणा